बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 79 ● नई दिल्ली ● शनिवार 03 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

नौसेना के जवानों ने परेड का किया अभ्यास, तस्वीरों में देखें अनुशासन और एकरूपता

दिल्ली । दक्षे में 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के तहत कर्तव्य पथ पर जवानों का व्यापक स्तर पर अभ्यास जारी है। कड़ाके की ठंड और सुबह के घने कोहरे के बीच भी देशभक्ति का उत्साह कम नहीं दिखा। शुक्रवार को भारतीय नौसेना के जवान अनुशासन, एकरूपता और अदम्य जोश के साथ परेड रिहर्सल करते नजर आए। जवानों का यह अभ्यास गणतंत्र दिवस समारोह की भव्यता और सशस्त्र बलों की तैयारियों का सशक्त संदेश देता है। गणतंत्र दिवस 2026 के उत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां तेज हो गई है। ऐतिहासिक लालकिला परिसर में 'भारत पर्व' के आयोजन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मंजूरी दे दी है। आयोजन 20 से 31 जनवरी 2026 तक ऑगस्ट क्रांति मैदान और ज्ञान पथ में आयोजित होगा।

उमर खालिद की रिहाई को लेकर अमेरिकी सांसदों ने लिखा लेटर, बीजेपी ने राहुल वाला कौन सा फोटो पोस्ट कर दिया?

नई दिल्ली । अमेरिकी सांसदों के एक समूह द्वारा भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर कार्यकर्ता उमर खालिद के लिए निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई की मांग करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ी आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पत्र के पीछे भारत विरोधी पैनल से जुड़े हुए हैं।

भाजपा, अमेरिकी सांसदों द्वारा भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जिसमें भारत से 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में पांच साल की जेल की सजा काट रहे खालिद को जमानत और निष्पक्ष सुनवाई देने का आग्रह किया गया था। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि जेन शाकोव्स्की, जो पत्र लिखने वाले आठ अमेरिकी सांसदों में शामिल थीं, ने 2024 में राहुल गांधी और भारत विरोधी इल्हान उमर के साथ मुलाकात की थी। गांधी को शाकोव्स्की, सैम पित्रोदा और अन्य लोगों के साथ दिख रही बैठक की एक तस्वीर साझा करते हुए, भाजपा नेता ने आरोप लगाया, जब भी विदेशों में भारत विरोधी बातें फैलाई जाती हैं, तो एक नाम राहुल गांधी बार-बार सामने आता है। भंडारी ने दावा किया कि 2024 में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, शाकोव्स्की ने अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया का मुकाबला अधिनियम पेश किया, जिसमें भारत का नाम लिया गया और मुस्लिम समुदायों पर कार्रवाई का आरोप लगाया गया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कार्यकर्ता उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने ''कड़वाहट'' को महत्व नहीं देने और स्वयं पर इसके हावी नहीं होने पर खालिद के विचारों को याद किया। ममदानी की इस चिट्ठी को खालिद की सहयोगी बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया था। खालिद को लिखी ममदानी की चिट्ठी की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था, ''जब जेल लोगों को अलग-थलग करने की कोशिश करती हैं तो आपके शब्द ताकत बनकर फैल जाते हैं।'' इस हाथ से लिखी चिट्ठी पर ममदानी के दस्तखत भी हैं। उन्होंने लिखा है, ''प्रिय उमर, मैं अक्सर आपके उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें कड़वाहट को खुद पर हावी नहीं होने देने की बात थी। आपके माता-पिता से मिलकर खुशी हुई। हम सब आपके बारे में ही सोच रहे हैं।'

पीएम मोदी ने दिलाई बुद्ध के आदर्शों की याद, प्रकाश और कमल प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ

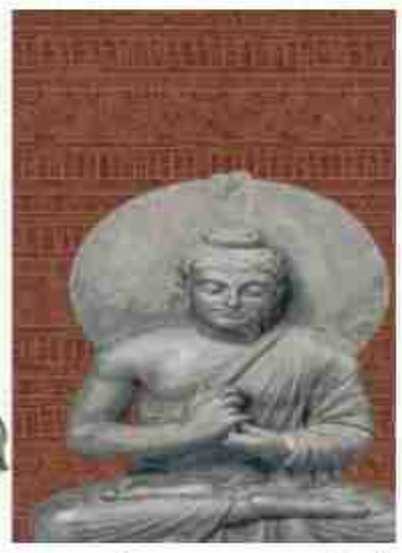

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 3 जनवरी को सुबह लगभग 11 बजे नई दिल्ली के राय पिथोरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष है, का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि कल, 3 जनवरी, इतिहास, संस्कृति और भगवान बुद्ध के आदर्शों के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए एक विशेष दिन है। सुबह 11 बजे, दिल्ली के राय पिथोरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, प्रकाश और कमल- जागृत व्यक्ति के अवशेष, का उद्घाटन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में पिपरावा के वे अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं जिन्हें एक सदी से अधिक समय बाद वापस लाया गया है।

साथ ही, पिपरावा के वे प्रामाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्रियां भी शामिल हैं जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के संग्रह में संरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने आगे कहा, यह हमारे युवाओं और हमारी समृद्ध संस्कृति के बीच संबंध को और गहरा करने का भी एक प्रयास है। मैं इन अवशेषों की वापसी के लिए काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, इस प्रदर्शनी में पहली बार एक सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए पिपरावा अवशेषों को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली और भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के संग्रहों में संरक्षित पिपरावा के प्रामाणिक अवशेषों और पुरातात्विक सामग्रियों के साथ प्रदर्शित किया गया है। 1898 में खोजे गए पिपरावा अवशेषों का प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में केंद्रीय स्थान है। ये भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पिपरावा स्थल को प्राचीन कपिलवस्तु से जोड़ते हैं, जिसे व्यापक रूप से उस स्थान के रूप में पहचाना जाता है जहां भगवान बुद्ध ने संन्यास लेने से पहले अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया था।

शिक्षकों का अपमान? केजरीवाल के ट्वीट पर दिल्ली सरकार का पलटवार, एफआईआर की तैयारी

नई दिल्ली । दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने शहर में शिक्षकों के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया है। इस मामले पर बोलते हुए सूद ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए गलत सूचना फैलाई, जिसके बाद सरकार ने गहन विचार-विमर्श के बाद एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया। एएनआई से बात करते हुए सूद ने कहा कि मैं दिल्ली के बेरोजगार नेताओं के बारे में यादा बात नहीं करता। सरकार ने दिल्ली में शिक्षकों के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने का सोच-समझकर फैसला लिया है। इस बार फर्जी खबर फैलाने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है, जो चंडीगढ़ के शीश महल में बैठा है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए यह गलत सूचना फैलाई। काफी विचार-विमर्श के बाद सरकार ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है। मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाली राय सरकार की कथित तौर पर निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों, स्कूलों और स्टेडियमों से आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और इस पर रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है। इस पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, या सड़कों पर कुत्तों की गिनती करेंगे? उन्होंने इस आदेश के जरिए शिक्षकों का अपमान करने के लिए भाजपा सरकार पर हमला किया। केजरीवाल ने लिखा कि भाजपा की दिल्ली सरकार का यह आदेश उनकी सोच और प्राथमिकताओं को उजागर करता है। भाजपा के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है; ये लोग शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं और स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा, केजरीवाल ने दिल्ली में भाजपा सरकार की तुलना में आप सरकार के शासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप ने शिक्षकों का सम्मान किया जबकि भाजपा सब कुछ नष्ट करने पर तुली हुई है।

घर के बाहर गाली गलौज करने से मना किया, नाबालिग ने दोस्त संग मिलकर 50 वर्षीय व्यक्ति को उतारा मौत के घाट

नई दिल्ली । दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में लालबाग क्षेत्र में एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, 50 वर्षीय व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई जब मृतक ने घर के बाहर गाली-गलौज कर रहे नाबालिगों को टोका था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी की तलाश जारी है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह के अनुसार, मृतक की पहचान बिहारी लाल के रूप में हुई है, जो पेशे से दर्जी थे और परिवार के साथ ए ब्लॉक लालबाग में रहते थे। घटना बृहस्पतिवार की रात की है। दो लड़के बिहारी लाल के घर के पास खड़े होकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। बिहारी लाल ने उन्हें डांटते हुए वहां से चले जाने के लिए कहा। इस बात से नाराज दोनों लड़के उग्र हो गए और उन्होंने बिहारी लाल को धक्का दिया। इसी दौरान, नाबालिग आरोपी ने बिहारी लाल पर चाकू से हमला कर दिया। परिजनों ने घायल बिहारी लाल को तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर उठाई सवाल, लाखों पेड़ कटने का दावा

नई दिल्ली ।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अत्यधिक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आक्रामक बुनियादी ढांचा निर्माण से जलवायु जोखिम बढ़ेगा, जन स्वास्थ्य को नुकसान होगा और स्थानीय समुदाय हाशिए पर चले जाएंगे। एएनआई से बात करते हुए रमेश ने नाजुक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को मंजूरी देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास पर्यावरण स्थिरता और लोगों के कल्याण की कीमत पर किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, मोदी सरकार इन परियोजनाओं को क्यों बढ़ावा दे रही है जो प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाती हैं और ऑक्सीजन को कम करती हैं? इससे किसे फायदा हो रहा है? लोगों को नहीं। स्थानीय समुदायों को नहीं। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर पर्यावरण संरक्षण की बजाय व्यापार करने में आसानी को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। रमेश ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मोदी सरकार व्यापार करने में आसानी के नाम पर सांस लेने और जीने की सहजता को क्यों नष्ट कर रही है। अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, उसे बाधित करते हैं, तो परिणाम वही होगा जो हमने सुनामी, बाढ़, भूकंप और भूस्खलन में देखा। उन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सरकार को अत्यंत असंवेदनशील बताया। उन्होंने आगे कहा कि जलवायु और पारिस्थितिकी के मामले में प्रधानमंत्री के कथनों और कार्यों में बहुत बड़ा अंतर है। रमेश ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पैदा की गई पर्यावरणीय आपदाओं की कोई कमी नहीं है। अभी हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर रोक लगा दी है। तो, यह मोदी सरकार द्वारा पैदा की गई एक आपदा थी, जिसे हमने सौभाग्य से फिलहाल टाल दिया है। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में मोदी सरकार द्वारा एक और बड़ी पर्यावरणीय आपदा पैदा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक साल से मैं पर्यावरण मंत्री को पत्र लिख रहा हूँ और संसद में कई बार यह मुद्दा उठा चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ हवाई अड्डा, बंदरगाह और पर्यावरण पर्यटन केंद्र बनने जा रहे हैं। वे ये सब बनाना चाहते हैं। यह एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा है। लाखों एकड़ जंगल काटे जाएँगे। एक लाख नहीं, दो लाख नहीं, तीन लाख नहीं, बल्कि लाखों पेड़ काटे जाएँगे। जैव विविधता को भारी नुकसान होगा। वहाँ के स्थानीय समुदाय, आदिवासी लोग विस्थापित हो जाएँगे। ग्राम सभा पहले ही कह चुकी है कि वे यह नहीं चाहते, फिर भी मोदी सरकार जबरदस्ती इस ग्रेट निकोबार अवसंरचना परियोजना को आगे बढ़ा रही है। रमेश की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय में आई हैं जब सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर, भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर, एक नए हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू करने का कदम उठाया है। एएनआई द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, यह कार्य आधिकारिक तौर पर 22 दिसंबर को शुरू हुआ।

महाराष्ट्र की राजनीति : राज्य का पवार परिवार हो या फिर ठाकरे कुनबा, एक होता नजर आ रहा है

राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहां कोई न तो स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। राजनीति में ऐसे कम ही उदाहरण मिलेंगे,जहां दोस्ती के मूल में दिल का रिश्ता होता है। गौर से देखें तो संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों की बुनियाद पर पर दोस्ती या दुश्मनी के रिश्ते आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के दो राजनीतिक परिवारों के मिलन को भी इसी अंदाज और संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राज्य का पवार परिवार हो या फिर ठाकरे कुनबा, अगर एक होता नजर आ रहा है या एक हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों परिवारों के प्रमुख अलंबरदारों के दिल मिल चुके हैं। बल्कि राजनीतिक संभावनाओं और अवसरों ने उन्हें एक होने को प्रेरित किया है। चाहे ठाकरे परिवार हो या फिर पवार कुनबा, दोनों में कुछ समानताएं हैं। शरद पवार हों या बाल ठाकरे, एक दौर में दोनों की महाराष्ट्र की राजनीति में तूती बोलती थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में तो राजनीतिक हलके का एक बड़ा हिस्सा शरद पवार को देश का भावी प्रधानमंत्री तक मानने लगा था। इसी तरह महाराष्ट्र के टाइगर के रूप में बाल ठाकरे की ख्याति रही। दोनों ही राजनीतिक खानदानों के मुखिया का स्वाभाविक उत्तराधिकारी दोनों के भतीजे ही माने जाते थे। एक दौर तक शरद के उत्तराधिकारी के तौर पर देश और प्रदेश अजित पवार को देखता था। इसी तरह शिवसैनिक भी बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे को अगली पीढ़ी का ठाकरे सीनियर मान चुका था। लेकिन जब उत्तराधिकार सौंपने की बारी आई तो पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले पर भरोसा जताया और बाल ठाकरे ने अपने छोटे बेटे राज ठाकरे को। ऐसे हालात में अजित और राज ठाकरे को अपना भविष्य चुनौतीपूर्ण लगा, राजनीतिक संभावनाएं कम होती दिखीं तो दोनों ने अपनी राह अलग कर ली। उन्नीस साल पहले राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली तो अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के मूल धड़े पर ही कब्जा कर लिया। पार्टी के असल संस्थापक शरद पवार पुछल्ला पार्टी लेकर एक तरह से किनारे का दल संभालने लगे। पवार परिवार और ठाकरे कुनबे में बिखराव की कहानी भी अलग-अलग रही। जब तक बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को बीजेपी के साथ खड़ा रखे, तब तक तो उनके नेतृत्व को चुनौती नहीं मिली। दल का राज्य में ठीकठाक समर्थन भी रहा। हालांकि महत्वाकांक्षाओं के साथ अलग हुए राज ठाकरे को राजनीतिक सफलताएं न के बराबर मिलीं। लेकिन जब से उद्धव ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस और पवार की एनसीपी का साथ पकड़ा, राजनीतिक मैदान में उसका आधार घटने लगा। वहीं पवार सीनियर से अलग होने के बावजूद बीजेपी के साथ के चलते अजित का राजनीतिक रुतबा कम नहीं हुआ। अलबत्ता कभी भारत के प्रधानमंत्री मैटेरियल देखे जाते रहे वरिष्ठ पवार की सियासी साख घटती चली गई। कुनबे में बिखराव के चलते दोनों परिवारों की राजनीतिक ताकत बीजेपी के सामने बौनी होती जा रही है।

एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों परिवारों के राजनीतिक अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगा है। एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। राजनीतिक अस्तित्व पर जब बन आती है तो कम ही सियासी हस्तियां होती हैं, जो समझौते नहीं करतीं। इसे समझदारी कहें या फिर राजनीति की रवायत, ठाकरे परिवार और पवार कुनबा-दोनों ही एक होने जा रहे हैं। पारिवारिक बिखराव को समेटने की कोशिश तेज हो गई है। ठाकरे बंधु तो बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस करके एक हो चुके हैं, जबकि पवार परिवार अपने गढ़ बारामती में एक होने का संकेत दे रहा है। बारामती में हाल ही में पवार परिवार ने एक आयोजन किया, जिसमें आज के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसे पवार कुनबे ने खूब प्रचारित किया। इस प्रचार का संदेश साफ है कि दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं। चाहे ठाकरे कुनबा हो या फिर पवार परिवार, अगर दोनों एक हो रहे हैं तो उसकी सिर्फ अस्तित्व की रक्षा भी नहीं है, बीजेपी रूपी चुनौती से पार पाना भी है और मुंबई महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका व पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका पर कब्जे की चाहत भी है। मुंबई महानगर पालिका का सालाना बजट करीब चौहत्तर हजार करोड़ रुपए का है। यह रकम उत्तर पूर्व के राज्यों के समूचे बजट से भी ज्यादा बैठती है। पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका के दायरे में एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जाहिर है कि यहां से कर के रूप में मोटी रकम आती है। ठाकरे परिवार की एकता के पीछे एक कारण जहां बृहन्नमुंबई महानगर पालिका पर कब्जा जमाना है, वहीं पवार परिवार की एकता के पीछे पुणे महानगरपालिका और पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका पर कब्जा जमाना है। दोनों परिवारों को लगता है कि अगर वे बिखरे रहे तो उनके प्रभाव वाली महानगरपालिकाओं में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यहां यह बताना जरूरी है कि एक दौर में बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहता था तो पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में पवार परिवार का। दोनों परिवारों के मिलन के पीछे की बड़ी वजह यही है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, अपने विस्तार के पहले चरण में वह अपने साथी दलों के सहयोग पर निर्भर रही। बाद के दौर में उसने खुद का प्रभाव बढ़ाया और अपने दम पर वह स्थापित होती चली गई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बाद अब इसी तरह वह महाराष्ट्र में वह अपने दम पर उभर चुकी है। जबकि कुछ साल पहले तक महाराष्ट्र में एक तरह से शिवसेना के छोटे भाई की भूमिका में रहती थी। अब चाहे शिवसेना का टूटा हुआ धड़ा हो या अजित पवार वाली एनसीपी, दोनों उसके छोटे भाई की भूमिका में हैं। जिस तरह निकाय चुनावों में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम किया है, उससे पवार परिवार की चिंताएं बढ़ी हैं और ठाकरे खानदान की भी। इसीलिए दोनों परिवार एक हुए हैं या होते नजर आ रहे हैं। पवार परिवार अब एक साथ पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के चुनाव में उतरने जा रहा है तो ठाकरे परिवार मुंबई में। लेकिन यह तय है कि दोनों परिवारों के रिश्तों की मजबूती इन महापालिका चुनाव नतीजों पर निर्भर करेगी। अगर उन्हें जीत मिली तो तय है कि पारिवारिक गठबंधन आगे बढ़ेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो दोस्ती की नई राह तलाशने की कोशिशें फिर से तेज होंगी।

सम्पादकीय...

बांग्लादेश

जब अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेश की घटनाओं को बर्बरता और नरसंहार बताया, मनोज जोशी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की बात कही, जया प्रदा ने हमारे मंदिरों को नष्ट किए जाने पर चिंता जताई, या आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि वे चुप नहीं रह सकते और न ही रहेंगे, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह घाव बहुत गहरा है। यह अब केवल सेलिब्रिटीज, राजनीति, कलाकारों या राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानव और राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने वाला मुद्दा बन चुका था। एक ऐसा अध्याय जो हमारे कभी के सहयोगी बांग्लादेश में हिंदुओं को अलग-थलग कर निशाना बनाए जाने और उनकी हत्या किए जाने पर फूट पड़ा। उसी बांग्लादेश में, जिसकी मुक्ति में भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। लेकिन यह इतिहास को भूलना है, ये अध्याय जो शेख मुजीबुर रहमान द्वारा लिखे गए, जिन्हें 'बंगबंधु' और बांग्लादेश के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है, और जिसे उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गढ़ा। समय के साथ एक ऐसा विमर्श उभरा कि भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का समर्थन मुख्यतः अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए किया, पाकिस्तान को कमजोर करने और विभाजित करने के उद्देश्य से। साथ ही, ऐसे स्वर भी कम नहीं थे जो भारत की भूमिका को मुक्ति संग्राम के विरोध में थे। तब से बहुत कुछ बदल चुका है। वर्तमान स्थिति वह है जहां बांग्लादेश भारत-विरोधी भावनाओं की आग में उलझा हुआ है, जहां भारत-बांग्लादेश संबंध अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता से बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार बने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई व्यवस्था आने के बाद नीतिगत बदलाव भी स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। यह तथ्य सर्वविदित है कि इसकी पृष्ठभूमि में भारत द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दिया जाना एक प्रमुख कारण रहा है। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब एक बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाई, जबकि भारत पर हसीना का समर्थन करने और हस्तक्षेपकारी एवं दबाव डालने वाला पड़ोसी होने के आरोप लगाए गए। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भारत-विरोधी भावना ने आग में घी का काम किया। हादी की 18 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई, जहां उनका इलाज चल रहा था। एक सप्ताह पहले ढाका में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे एक नकाबपोश व्यक्ति ने उनके सिर में गोली मार दी थी। हादी की मृत्यु के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद आगजनी की घटनाएं हुईं, इमारतों को आग के हवाले किया गया और मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया गया। यह उल्लेखनीय है कि हादी भारत और शेख हसीना के साथ उसकी करीबी के मुखर आलोचक थे। उनकी हत्या के बाद भारत-विरोधी प्रदर्शन और तेज हो गए, खासकर उन दावों के बाद कि हादी पर गोली चलाने वाले शूटर्स को भारत में शरण मिली। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संदिग्ध फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख स्थानीय सहयोगियों की मदद से भारत के मेघालय राज्य में दाखिल हुए। वे हलुआघाट सीमा के रास्ते भारत आए और फिर उन्हें मेघालय के तुरा शहर ले जाया गया।- स्वाभाविक और उचित रूप से, भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जहां एक ओर बांग्लादेश में भारत-विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे थे, वहीं दीपू दास नामक एक हिंदू को उग्र भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। दीपू दास के लिए न्याय की मांग को लेकर भारत के कई हिस्सों में प्रमुख हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। हाथों में तख्तियां और बैनर दिखाई दिए, जिन पर नारे लिखे थे, 'बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भारत बर्दाश्त नहीं करेगा'। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए, नई दिल्ली और ढाका, दोनों सरकारों ने पारस्परिक रूप से वीजा सेवाओं को निलंबित करने का कदम उठाया। इस फैसले का असर उन हजारों बांग्लादेशी नागरिकों पर पड़ा जो इलाज के लिए भारत आते थे, जिससे यह मामला मानवीय संकट का रूप लेने लगा। उल्लेखनीय है कि भारत प्रतिदिन लगभग 1,500 वीजा जारी करता था, जिनमें चिकित्सा और आपातकालीन वीजा को प्राथमिकता दी जाती थी। एक अन्य स्तर पर, प्रदर्शनकारियों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की ओर मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किए, जिससे गंभीर सुरक्षा चिंताएं उत्पन्न हो गईं। इस बीच भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ चरमपंथियों द्वारा की जा रही निरंतर शत्रुता अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। हम मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की हालिया निर्मम हत्या की निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। विशेषज्ञों ने इन बढ़ते तनावों को खतरनाक स्तर का बताया है। हालांकि, भारत में यह व्यापक सहमति है कि इस संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता है। बांग्लादेश में आम चुनाव फरवरी 2026 में होने हैं। ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान की एंट्री होती है। 17 वर्षों के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। उनकी घर वापसी पर उमड़े उत्साही और विशाल जनसमूह, इस ओर संकेत करते हैं कि आगामी चुनावों में बीएनपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अपनी ओर से, तारिक रहमान ने जूते उतारकर मातृभूमि की धरती पर नंगे पांव कदम रखा, यह उस भूमि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक था, जिसे कोई अत्यंत प्रिय और पवित्र मानता है। हम ऐसा बांग्लादेश बनाएंगे, जिसका सपना एक मां देखती है, उन्होंने कहा और मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों तथा ईसाइयों से एक समावेशी राष्ट्र के निर्माण में उनके साथ जुड़ने का आह्वान किया। -मेरे पास एक योजना है। अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए- रहमान ने कहा। लेकिन जब रहमान को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अग्रणी माना जा रहा है, तब सवाल उठता है कि इस 'योजना' में भारत की भूमिका कहां और किस रूप में है, या क्या है भी? भारत के लिए चेतावनी के संकेत कौन-से हैं? या फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं, के लिए क्या खतरे मौजूद हैं? निस्संदेह, रहमान का सभी के लिए -सुरक्षा के अधिकार- का आह्वान नई दिल्ली में सकारात्मक गूंज पैदा करता है और कुछ हद तक आश्वस्त भी करता है, लेकिन क्या यह हिंदुओं के लिए सुरक्षित माहौल की गारंटी देता है? क्या वे वास्तव में बांग्लादेश में सुरक्षित रह पाएंगे? यदि बीएनपी सत्ता में आती है, तो शेख हसीना के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध द्विपक्षीय रिश्तों को किस तरह प्रभावित करेंगे?

पढ़ाई से लेकर खेल तक

भारत में बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम एक गंभीर चिंता का विषय है। अक्सर हमने अपने आसपास और घरों में देखा है कि बच्चे अब बाहर खेलने के बजाय अपना अधिकतर समय मोबाइल के इस्तेमाल में लगा रहे हैं। पढ़ाई से लेकर खेल और दोस्ती तक, सब कुछ स्क्रीन के जरिए होने लगा है। आमतौर पर शहरों में रहने वाले बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा देखा गया है जिससे उनके पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है। कई माता-पिता का मानना है कि बच्चों द्वारा मोबाइल का बढ़ता इस्तेमाल उनके व्यवहार में भी बदलाव ला रहा है। बच्चों के माता-पिता का कहना है कि उनके बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं। बच्चे बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया, गेमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक चिंता का विषय है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा दिया। अब यह कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य में रुकावट बन रहा है। बच्चे अब पढ़ाई और खेल मैदान से दूर होते जा रहे हैं। समय-समय पर प्रबुद्ध लोगों ने मोबाइल फोन के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की लत युवाओं को न केवल पढ़ाई से दूर कर रही है, बल्कि युवा वर्ग खेल के मैदान से भी दूर होता जा रहा है। अभिभावकों को इस विषय पर ध्यान देने की खासी जरूरत है। लाड़-प्यार में बच्चों और युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। हाल ही में हुए एक सर्वे से चौंकाने वाली बात सामने आई है। भारत के लगभग 302 शहरी स्थानों या जिलों में बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को लेकर किए गए इस सर्वे के मुताबिक, आधे से ज्यादा माता-पिता ने माना कि उनके बच्चे दिन में 3 घंटे से ज्यादा समय मोबाइल पर बिता रहे हैं। सर्वे के मुताबिक, लगभग 70 प्रतिशत माता-पिता का मानना है कि उनके बच्चे मोबाइल पर यूट्यूब, स्ट्रीमिंग वीडियो और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 6-7 प्रतिशत माता-पिता ने सर्वे के दौरान यह भी स्वीकार किया कि मोबाइल और सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से बच्चों के व्यवहार में बदलाव आया है। उनके अनुसार बच्चे अब ज्यादा चिड़चिड़े, गुस्सैल और मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहे हैं। स्क्रीन मासूमियत ही नहीं छीन रही है, बेचैनी, ध्यान की कमी, नींद से जुड़ी समस्याएं, चिड़चिड़ापन भी दे रही है। स्कूल से फोकस घट रहा है। यही वजह है कि हाल में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के किशोर-बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून बनाने का सुझाव दिया है। भारत में दस साल से कम उम्र के बच्चों तक के सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए हैं। ऐसे दौर में जब बच्चे डिजिटल मीडिया को अंतिम सत्य मानने लगे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य बनाना एक सुखद अहसास ही है। सुबह की प्रार्थना के दौरान दस मिनट तक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खबरें व संपादकीय पढ़ना अनिवार्य किया गया है। बाकायदा रोज पांच कठिन शब्द अर्थ के साथ ब्लैकबोर्ड पर दर्ज होंगे। निश्चय ही इस प्रयास से जहां बच्चों में पढ़ने की संस्कृति, शब्द व सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, वहीं उनके स्क्रीन टाइम में कमी आ सकेगी। निर्विवाद रूप से इससे धीरे-धीरे छात्रों की पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बच्चे पढ़ने की संस्कृति से जुड़कर भावनात्मक, बौद्धिक व सामाजिक सरोकारों से समृद्ध होंगे। बहुत संभव है कि यदि इस अभियान को निरंतरता के साथ चलाया जाता रहा तो बच्चे पुस्तकालयों में रुचि लेने लगेंगे। विडंबना यह है कि आज बच्चों की उंगलियां पुस्तकों के पन्ने पलटने के बजाय मोबाइल के की-बोर्ड पर थिरकती रहती हैं। स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यार्थियों को मासिक या त्रैमासिक स्कूल समाचार पत्र अथवा पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करें। कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए संपादकीय लेखन या समूह चर्चा आयोजित की जाए। 'क्रॉसवर्ड' और 'सुडोकू' प्रतियोगिताएं कराई जाएं तथा कनिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों में अखबारों की कटिंग से 'स्क्रैपबुक' बनाने की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। चिंताजनक स्थिति है कि भारत में पांच साल तक के बच्चे भी रोज दो घंटे से अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं। अखबार केवल सूचनाएं नहीं पहुंचाते, समझ, संवेदनशीलता और सामाजिकता भी पैदा करते हैं। इस तरह के आदेश की नौबत आना ही बताता है कि बच्चों में स्क्रीन की लत किस कदर गंभीर हो चुकी है। पढ़ने का मतलब केवल कोर्स की किताबें नहीं होतीं। डिजिटल दौर में सूचनाएं हर तरफ से आ रही हैं लेकिन उनमें कौन-सी सही है और कौन गलत,यह समझना चुनौती है। अखबार आज भी सबसे भरोसेमंद माध्यम हैं। इनको पढ़ने से बच्चों को विश्वसनीय जानकारी मिलेगी, विभिन्न घटनाओं को लेकर उनका अपना नजरिया बनेगा और भाषा में सुधार होगा। प्रायः ऐसे प्रयासों को यह कहकर खारिज किया जाता है कि 'स्कूली बच्चों का खबरों की दुनिया से कोई लेना-देना नहीं होता, लिहाजा उन्हें सिर्फ पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।' वास्तव में यह धारणा सही नहीं है। भले ही अखबारों में छपने वाली खबरों का स्कूली पढ़ाई और परीक्षाओं से ज्यादा संबंध न हो लेकिन उन्हें पढ़ने-सुनने से विद्यार्थियों के सोचने-समझने का नजरिया बदलता है। चाहे उन्हें शुरुआत में कई खबरें समझ में न आएं। एक समय ऐसा आएगा, जब वे खबरों में रुचि लेने लगेंगे। उनकी समझ बढ़ेगी। आज स्कूलों में कई बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें फिल्मी सितारों के बारे में तो बहुत कुछ मालूम है। वे देश के प्रमुख पदों पर सेवारत लोगों के नाम नहीं जानते। ये बच्चे जब भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। इन्हें सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के बारे में कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं। इसमें काफी समय लगता है।

चीन-रूस गठजोड़ के और अधिक मजबूत होने का नवीनतम उदाहरण

चीन और रूस अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं और आक्रामक कदम उठा रहे हैं, जिनके अमरिका के लिए गंभीर परिणाम हो रहे हैं। 9 दिसम्बर को, चीनी और रूसी बमवर्षक विमानों और अन्य विमानों ने जापान और दक्षिण कोरिया के निकट उड़ान भरी, जिससे अमरीका और जापान को लड़ाकू विमानों और बमवर्षक विमानों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना चीन-रूस गठजोड़ के और अधिक मजबूत होने का नवीनतम उदाहरण है। बीजिंग और मॉस्को अमरीका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और अमरिका और उसके सहयोगियों की कीमत पर अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते हैं। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने बार-बार कहा है कि उनकी साझेदारी की कोई सीमा नहीं है और वे 40 से अधिक बार आमने-सामने मिल चुके हैं। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से, चीन ने रूस को 'उच्च प्राथमिकता वाली वस्तुओं' का निर्यात बढ़ा दिया है, जिनमें 50 दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कम्प्यूटर चिप्स, मशीन टूल्स, राडार और सैंसर, जिनकी रूस को युद्ध जारी रखने के लिए आवश्यकता है। चीन के निर्यात ने रूस को 2023 से 2024 तक इस्कंदर-एम बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन 3 गुना बढ़ाने में मदद की, जिनका उपयोग रूस ने यूक्रेनी शहरों पर बमबारी करने के लिए किया है। 2024 में, रूस द्वारा आयात किए गए अमोनियम परक्लोरेट का 70 प्रतिशत हिस्सा चीन का था, जो बैलिस्टिक मिसाइल ईंधन का एक आवश्यक घटक है। चीन ने रूस को ड्रोन बॉडी, लिथियम बैटरी और फाइबर-ऑप्टिक केबल प्रदान किए हैं, जो यूक्रेन में इस्तेमाल किए जाने वाले फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन के लिए महत्त्वपूर्ण घटक हैं, जो इलैक्ट्रॉनिक जैमिंग को बाईपास कर सकते हैं। इस सहयोग से चीन को लाभ हो रहा है। रूस ने उन्नत प्रणोदन प्रणाली उपलब्ध कराकर चीन की अगली पीढ़ी की टाइप 096 परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के विकास में संभवतः सहायता की है। लीक हुए दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि रूस ने ताइवान पर आक्रमण में इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपकरण, जैसे हल्के उभयचर वाहन, स्वचालित एंटी-टैंक तोपें, हवाई बख्तरबंद कार्मिक वाहक और हवाई मार्ग से पैराशूट गिराने के लिए विशेष प्रयोजन वाली प्रणालियां चीन को बेचने पर सहमति जताई थी। 2017 और 2024 के बीच, उन्होंने एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व, आर्कटिक और अफ्रीका सहित एक विस्तृत क्षेत्र में लगभग 100 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए हैं। इन देशों ने कई प्रशिक्षण मिशन भी आयोजित किए हैं, जिनमें 2019 और 2024 के बीच 8 संयुक्त बमवर्षक उड़ानें शामिल हैं। जुलाई 2024 में, चीन और रूस ने अलास्का के तट पर संयुक्त गश्त के दौरान क्रमशः शीआन एच-6 और टू-95 बियर नामक लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों को उड़ाया। भविष्य में, रूस चीन को जमीन और अंतरिक्ष आधारित मिसाइल चेतावनी प्रणालियों के विकास में मदद कर सकता है, जिससे चीन की मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता बढ़ेगी और नई प्रणालियों के विकास में तेजी आएगी।

पर्यावरण संरक्षण, अल्पसंख्यक अधिकार,शरणार्थी संवेदनशीलता ये सब सनमुख दृष्टि के बिना संभव नही

वैश्विक स्तरपर मनुष्य का जीवन केवल उसकी शिक्षा, धन या पद से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से संचालित होता है।इतिहास गवाह है कि जिन व्यक्तियों, समाजों और राष्ट्रों ने अपने स्वभाव को अनुशासन, नैतिकता और उच्च मूल्यों से जोड़ा, वे दीर्घकालीन सफलता के प्रतीक बने।भारतीय दर्शन में मानव स्वभाव को समझाने के लिए मनमुख, गुरमुख और सनमुख जैसे गहन और सार्वकालिक सिद्धांत दिए गए हैं। ये अवधारणाएँ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैश्विक मानव व्यवहार विज्ञान की भी कसौटी पर खरी उतरती हैं। आज जब विश्व नेतृत्व संकट, नैतिक पतन, मानसिक तनाव और मूल्य-संक्रमण से गुजर रहा है, तब इन स्वभावों का विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रासंगिक हो जाता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता केवल उसके संविधान की सुंदर भाषा या संस्थाओं की मजबूती से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके नागरिकों का स्वभाव कैसा है। संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, परंतु यह अपेक्षा भी करता है कि नागरिक विवेकशील,उत्तरदायी और नैतिक होंगे। जब नागरिक मनमुख स्वभाव से संचालित होते हैं, तो लोकतंत्र अधिकारों की भीड़ बन जाता है; और जब वे गुरमुख व सनमुख होते हैं, तो लोकतंत्र लोक-कल्याण का जीवंत तंत्र बनता है। साथियों बात अगर हम मनमुख से गुरमुख सनमुख की यात्रा को संविधान, लोकतंत्र और नागरिकता के संदर्भ में समझने की करें तो (1) मनमुख स्वभाव और लोकतंत्र का क्षरण-मनमुख नागरिक वह है जो संविधान को केवल अपने हित के औज़ार की तरह देखता है। उसे अधिकार याद रहते हैं,कर्तव्य नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो लोकतंत्रों में बढ़ता ध्रुवीकरण, हिंसक असहमति, टैक्स चोरी, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग, ये सभी मनमुख नागरिकता के लक्षण हैं। जब,मैं राष्ट्र से ऊपर हो जाता है, तब संविधान की आत्मा कमजोर पड़ती है। (2) गुरमुख नागरिकता- संवैधानिक विवेक की नींव गुरमुख नागरिक संविधान को अपना नैतिक गुरु मानता है। वह कानून के शब्दों के साथ-साथ उसके उद्देश्य को भी समझता है,न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ऐसा नागरिक मतदान को केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी मानता है। विश्व के सफल लोकतंत्रों में नागरिकों का यही गुरमुख स्वभाव संस्थाओं को मजबूत बनाता है। (3) सनमुख लोकतंत्र अधिकार से आगे मानवता सनमुख नागरिकता लोकतंत्र को केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं रखती,बल्कि उसे वैश्विक मानवता से जोड़ती है। पर्यावरण संरक्षण, अल्पसंख्यक अधिकार,शरणार्थी संवेदनशीलता ये सब सनमुख दृष्टि के बिना संभव नहीं। यही दृष्टि संविधान को मानव गरिमा का वैश्विक दस्तावेज़ बनाती है।इसलिए हम कर सकते हैं कि यदि नागरिक मनमुख रहेंगे, तो संविधान केवल किताब बनेगा; यदि नागरिक गुरमुख बनेंगे, तो संविधान व्यवस्था बनेगा;और यदि नागरिक सनमुख बनेंगे, तो संविधान मानवता का पथप्रदर्शक बनेगा। साथियों बात अगर हम,मनमुख से गुरमुख, सनमुख की यात्रा को भारत के भविष्य युवाओं से जोड़कर समझने की करें तो, युवा ही राष्ट्र का स्वभाव हैं। आज का युवा केवल कल का नागरिक नहीं, बल्कि आज का निर्णायक है। उसका स्वभाव तय करेगा कि भविष्य में राष्ट्र कैसा होगा। यदि युवा मनमुख है, तो तकनीक भी विनाश का औज़ार बनेगी; और यदि युवा गुरमुख-सनमुख है, तो वही तकनीक मानवता की सेवा करेगी। (1) मनमुख युवा-तात्कालिक सफलता का भ्रम-आज का युवा यदि केवल त्वरित प्रसिद्धि, आसान पैसा और सोशल मीडिया की वाहवाही के पीछे भागता है, तो वह मनमुखता की ओर बढ़ रहा है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानसिक तनाव,अवसाद और उद्देश्यहीनता इसी का परिणाम है। मनमुख युवा प्रतियोगिता तो जीतना चाहता है, पर धैर्य नहीं रखना चाहता। (2) गुरमुख युवा कौशल के साथ संस्कार-गुरमुख युवा वह है जो सीखने को गुरु मानता है,शिक्षक,अनुभव, असफलता और अनुशासन को।वह जानता है कि वास्तविक सफलता रातों-रात नहीं आती। विश्व के नवाचार, स्टार्ट-अप और शोध नेतृत्व इसी स्वभाव से निकले हैं। (3) सनमुख युवा- करियर से आगे योगदान- सनमुख युवा अपने करियर को समाज से जोड़ता है। वह पूछता है-मैं क्या बनूँ? के साथ-साथ मैं किसके काम आऊँ ? यही युवा जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता और शांति प्रयासों में नेतृत्व करता है। साथियों बात अगर हम,मनमुख से गुरमुख, सनमुख की यात्रा को प्रशासनिक, आध्यात्मिक समन्वित स्थिति सुशासन का बाहरी अनुशासन और आत्मशासन की आंतरिक शक्ति इस रूप में समझने की करें तो, शासन की गुणवत्ता शासक के स्वभाव से ही अधिक सफल होने की संभावना रखती है,प्रशासन केवल नियमों से नहीं, बल्कि प्रशासक के स्वभाव से चलता है। इतिहास बताता है कि जब प्रशासक मनमुख होता है, तो नियम भी भ्रष्ट हो जाते हैं; और जब वह गुरमुख-सनमुख होता है, तो सीमित संसाधनों में भी सुशासन संभव हो जाता है।(1) मनमुख प्रशासन-सत्ता का अहंकार -मनमुख प्रशासक पद को अधिकार समझता है, सेवा नहीं। इससे लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और जन-अविश्वास जन्म लेता है। वैश्विक स्तर पर प्रशासनिक विफलताओं का मूल कारण यही स्वभाव है।(2) गुरमुख प्रशासन-नियम +विवेक गुरमुख प्रशासक नियमों को गुरु मानता है, पर विवेक से काम लेता है। वह संविधान, कानून और नीति को आत्मसात करता है। ऐसे प्रशासन में नागरिकों का विश्वास बढ़ता है और संस्थाएँ सशक्त होती हैं। (3) सनमुख नेतृत्व- सत्ता से सेवा तक- सनमुख प्रशासक सत्ता को साधना मानता है। वह निर्णय लेते समय सबसे कमजोर व्यक्ति को ध्यान में रखता है। यही आध्यात्मिक चेतना प्रशासन को मानवीय बनाती है,जहाँ फाइलों के पीछे चेहरे दिखते हैं। साथियों बात हम मनमुख,गुरमुख और सनमुख स्वभाव को समझने की करें तो, (1) मनमुख स्वभाव का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने मन, इच्छा, वासना, अहंकार और तात्कालिक लाभ के अनुसार निर्णय लेता है। वह न तो विवेक को महत्व देता है, न ही गुरु, समाज, शास्त्र या नैतिक मूल्यों को। आधुनिक वैश्विक संस्कृति में यह स्वभाव उपभोक्तावाद भोगवाद और अति-व्यक्तिवाद के रूप में व्यापक रूप से दिखाई देता है।राजनीति और शासन में मनमुख प्रवृत्ति के दुष्परिणाम व त्रासदी भयंकर प्रमाण में होती है।अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब शासक मनमुख स्वभाव से निर्णय लेते हैं, तो सत्ता अहंकार, भ्रष्टाचार और युद्ध को जन्म देती है। इतिहास में कई साम्राज्य केवल इसलिए गिरे क्योंकि उनके नेतृत्व ने जनकल्याण की बजाय व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को चुना। यह स्वभाव राष्ट्रों को भी अस्थिर कर देता है। (2) गुरमुख स्वभाव का अर्थ है,गुरु,विवेक,ज्ञान और नैतिक मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीना। यहाँ 'गुरु' केवल व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि सत्य, अनुभव, संविधान, नैतिकता और सामूहिक विवेक का प्रतीक है। गुरमुख व्यक्ति अपने मन को अनुशासित करता है, न कि उसका दास बनता है।जब शासन गुरमुख स्वभाव से चलता है, तो नीति-निर्माण में पारदर्शिता, जवाबदेहीऔर न्याय प्राथमिकता बनते हैं। संविधान भी एक प्रकार का 'गुरु' है, जो सत्ता को मर्यादा में रखता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुशासन के सफल मॉडल इसी सिद्धांत पर आधारित हैं।(3) सनमुख स्वभाव का अर्थ है,सत्य, सद्गुण, सेवा और सार्वभौमिक मानव मूल्यों की ओर उन्मुख होना। यह स्वभाव गुरमुख से भी आगे जाकर व्यक्ति को स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा पर ले जाता है। यहाँ व्यक्ति केवल अपने या अपने समाज के बारे में नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के बारे में सोचता है। आज जब जलवायु परिवर्तन, युद्ध, शरणार्थी संकट और असमानता जैसी वैश्विक समस्याएँ सामने हैं, तब सनमुख स्वभाव की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यह स्वभाव 'वसुधैव कुटुम्बकम' को व्यवहार में उतारता है।अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठनों चिकित्सकों शिक्षकों और स्वयंसेवकों में यह स्वभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही स्वभाव विश्व को अधिक मानवीय बनाता है।सनमुख स्वभाव किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक नैतिक चेतना है, जो आधुनिक विज्ञान, तकनीक और विकास के साथ भी सामंजस्य बिठा सकती है। यह व्यक्ति को भीतर से मजबूत और बाहर से उपयोगी बनाता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सुशासन यानें बाहरी अनुशासन (कानून) आंतरिक अनुशासन यानें स्वभाव,मनमुख से सत्ता बिगड़ती है,गुरमुख से व्यवस्था चलती है,और सनमुख से इतिहास बनता है।आओ,मनमुख स्वभाव छोड़ेंगुरमुख बनकर विवेक अपनाएंसनमुख बनकर मानवता को प्राथमिकता दें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीपलमैनला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/0882)

24 साल से वेतन-पेंशन नहीं, 96 पूर्व सैनिकों ने दिल्ली में फूंका आंदोलन का बिगुल

दाभोल/एनटीपीसी मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन धरना

नई दिल्ली , (ए.के.चौधरी) दाभोल/एनटीपीसी से जुड़े 96 पूर्व सैनिकों ने शुक्रवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 24 वर्षों से लंबित वेतन और पेंशन के मुद्दे पर सरकार और संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। पूर्व सैनिकों ने साफ शब्दों में कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा और यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे।

मुंबई से आए वरिष्ठ पूर्व सैनिकों ने मीडिया के सामने पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज पेश किए। उन्होंने बताया कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद संबंधित संस्थानों ने न तो वेतन दिया और न ही पेंशन। इसका सीधा असर आज उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। कई पूर्व सैनिक बुजुर्ग हो चुके हैं और इलाज, भोजन व आवास जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पूर्व सैनिकों ने कहा कि “जय हिंद, जय जवान” उनके लिए केवल नारा नहीं, बल्कि पहचान है। लेकिन आज वही सैनिक अपने हक के लिए सड़कों पर आने को मजबूर हैं। वक्ताओं ने इसे सिस्टम की गंभीर विफलता बताया।

प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने लगातार सवाल किए, तो कई पूर्व सैनिक भावनात्मक हो गए। 24 वर्षों के इंतजार और लगातार संघर्ष की पीड़ा शब्दों में उतर आई। इसी भावनात्मक क्षण में कुछ पूर्व सैनिकों ने यह कहते हुए अपने ऊपरी कपड़े उतारकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया कि अब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि मौके पर मौजूद कई पत्रकार भी भावुक हो उठे और उनकी आंखें नम हो गईं। पत्रकारों ने एक स्वर में भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे और पूर्व सैनिकों की यह आवाज देश-दुनिया तक पहुंचाएंगे। पूर्व सैनिकों ने यह भी बताया कि दाभोल/एनटीपीसी मुख्यालय के सामने प्रस्तावित कार्यक्रम में भी पत्रकारों ने उपस्थित रहने और आंदोलन को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

पूर्व सैनिक लक्ष्मण महाडिक ने कहा कि 24 साल किसी भी व्यक्ति के जीवन का बड़ा हिस्सा होते हैं। “हमने सेवा दी, लेकिन बदले में सिर्फ टालमटोल मिली। अब सब्र खत्म हो चुका है।”

सूर्यकांत पवार ने कहा कि यह मामला भावनात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह दस्तावेज़ों पर आधारित है। “हमने आज सारे रिकॉर्ड मीडिया के सामने रख दिए हैं। अब जवाबदेही तय होनी चाहिए।”

पूर्व सैनिक आर. जी. पवार ने सवाल उठाया कि देश के लिए काम करने वाले सैनिक आखिर किस हाल में पहुंच गए हैं। हर युद्ध जीतने वाले सैनिक आज रोटी, कपड़ा और दवा के लिए जूझ रहे हैं।

वी. एस. सालुंखे ने साफ चेतावनी दी कि अब संघर्ष टालना संभव नहीं है।

“हम सभी संवैधानिक रास्ते अपना चुके हैं। अब न्याय मिलेगा या आंदोलन तेज होगा।”

प्रेस वार्ता के दौरान सुरेश पलपुटे ने मीडिया से अपील की कि इस मुद्दे को दबने न दिया जाए।

“अगर आज भी आवाज नहीं उठी, तो यह संदेश जाएगा कि सैनिकों के अधिकारों की कोई अहमियत नहीं है।”चंद्रकांत शिंदे ने कहा कि यह लड़ाई अब सिर्फ 96 लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 96 परिवारों के भविष्य का सवाल बन चुकी है।

वहीं विजय निकम ने आगे की रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, तो दाभोल/एनटीपीसी मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।

पूर्व सैनिकों ने दोहराया कि वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन 24 वर्षों की लगातार उपेक्षा ने उन्हें निर्णायक कदम उठाने के लिए मजबूर किया है।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया

लखनऊ ।

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन (एसआईओ) की ओर से मौलवी गंज स्थित कार्यालय में बच्चों की हौसला-अफजाई और शैक्षणिक विकास के उद्देश्य से एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 30 दिसंबर को एस० आई० ओ० लखनऊ द्वारा बच्चों के बीच कुरआन मजीद की चयनित सूरतें अनुवाद सहित याद करने की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत कारी रूहुल अमीन की पवित्र कुरआन की तिलावत से हुई। इस अवसर पर साकिब ए आलम खैराबादी ने बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षा, कुरआन से जुड़ाव और नैतिक प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एडवोकेट मोहम्मद राशिद ने बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं, जिस उम्र में उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं, उसी के अनुसार उनका व्यक्तित्व निखरता है। उन्होंने कहा कि एस० आई० ओ० बच्चों की बौद्धिक और नैतिक तरक्की के लिए समय-समय पर इस तरह की शैक्षणिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। प्रतियोगिता में ज़िवान ने प्रथम, अयान ने द्वितीय और अरशिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में कुल 40 बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। हाफ़िज़ नज़रुल इस्लाम की दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर रुवैद फलाही, अमजद फलाही, हाफ़िज़ तालिब, अरमान इदरीसी, अब्दुल अज़ीम आदि उपस्थित रहे।

18 फरवरी से होंगी बोर्ड परीक्षा, 117 केन्द्रों में 66,429 विद्यार्थी देंगे परीक्षा

फतेहपुर।

माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) द्वारा घोषित बोर्ड परीक्षा 2026 कार्यक्रम के अनुसार जनपद में 18 फरवरी से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। इस बार जिले में कुल 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले अनंतिम सूची में 109 केंद्र प्रस्तावित थे, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण के बाद आठ नए केंद्र बढ़ाए गए, जिससे केंद्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि बोर्ड के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त 123 आपत्तियों के परीक्षण और निस्तारण के बाद बोर्ड ने अंतिम सूची जारी कर दी, जिसमें 117 केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालयवार छात्र आवंटन सहित पूरी सूची पोर्टल पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि भले ही इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या पिछले सत्र से कम है, फिर भी नकलविहीन और सुचारु परीक्षा संचालन के उद्देश्य से केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। पिछले सत्र में जहां 105 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, वहीं इस बार 117 केंद्रों पर परीक्षाएं कराई जाएंगी।

परीक्षार्थियों का पूरा ब्योरा
कुल पंजीकृत परीक्षार्थी: 66,429
हाईस्कूल: 36,698
इंटरमीडिएट: 29,731

केंद्रों के अंतिम रूप से तय होते ही शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 18 फरवरी से जनपद के 117 परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षाओं का आगाज होगा, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

महिषासुर मर्दिनी मंदिर में हुई चोरी का हुआ सफल अनावरण, अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

बहराइच। प्रेमनाथ तिवारी पुत्र स्व0 घनश्याम तिवारी निवासी मोहल्ला कानूनगोपुरा उत्तरी थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच(एडवोकेट प्रबन्धक नानक शाही धर्म रक्षा समिति जोशियापुरा बहराइच) द्वारा सूचना दिया गया कि मोहल्ला जोशियापुर में स्थित महिषासुर मर्दिनी मंदिर में किसी अज्ञात चोर द्वारा मंदिर के पीछे की जाली तोड़ कर बड़ा पीतल का घन्टा , दान पात्र की कुन्डी तोड़ कर उसमें रखा चढ़ावा , पूजा के बर्तन थाली व तांबे का लोटा चोरी कर लिया गया है। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 276/25 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह को आवंटित की गयी । घटना के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण द्वारा दिये निर्देश के क्रम में उ0नि0 देवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह हे0का0 सुरेन्द्र कुमार यादव द्वारा घटना कारित वाले अभियुक्त पुलकित मिश्रा पुत्र सुशील कुमार मिश्रा निवासी छिंगिहा थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया एक अदद बड़ा पीतल का घंटा, एक अदद तांबे की थाली, 03 अदद तांबे का लोटा व 770 रूपये नगद बरामद किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घर के पीछे लगे समर सेबल को चोरों ने किया पर लोगों में आक्रोश

मेजा ,प्रयागराज। मेजा थाना क्षेत्र स्थित रामनगर चौकी अंतर्गत चौखठा गौरा औता गांव में बृहस्पतिवार बीती रात को केपी तिवारी के घर के पीछे लगे समरसेबल को चोरों ने किया पार। सुबह जब परिजन सो कर उठे जब समरसेबल चालू करने लगे तो नहीं चालू हुआ जब गए देखे तो घर के पीछे लगा समरसेबल नहीं था आनन फानन में परिजन डायल हंड्रेड को सूचना दी पीआरवी पुलिस मौके पहुंचकर जांच पड़ताल कर चली गई। परिजनों कहना है कि घर से 300 मीटर की दूरी पर सबमर्सेबल चोरों ने चोरी कर के लें गए है । परिजनों ने लिखी शिकायत रामनगर चौकी पर दिया है घर के सदस्य सभी मुंबई रहते हैं घर पर सिर्फ महिलाएं थी इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने समरसेबल खोल ले गए जिससे ग्रामीणों मे आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव मे कई बार चोरियां हो चुकी लेकिन पुलिस खुलासा करने में नाकाम रहती है। शासन प्रशासन से परिजनों व ग्रामीणों की मांग है कि मांग की चोरी का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए।

नवादा गांव के राजा बाबू का सेना में चयन, विधायक ने घर पहुंचकर दी बधाई

बिलारी। नवादा गांव निवासी राजा बाबू के भारतीय सेना में टेक्निकल सुपरवाइजर पद पर चयन होने से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। इस उपलब्धि पर विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने राजा बाबू के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने कहा कि राजा बाबू की सफलता गांव व क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने आशा जताई कि राजा बाबू देश सेवा के अपने दायित्व को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। इस अवसर पर ग्राम प्रधान इस्लाम, रवि , बसंत कुमार, उस्मान, विश्वजीत सिंह यादव, रूप किशोर ,शिशुपाल यादव, एपी यादव, दिनेश जाटव आदि भी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने भी राजा बाबू की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

हर हाल में रोका जाये ई-वेस्ट का ट्रांसपोर्ट: डीएम

अधिकारियों को दिये निर्देश

मुरादाबाद।

डीएम अनुज कुमार सिंह ने ई-वेस्ट के ट्रांसपोर्ट को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने पुलिस, प्रशासन, आरटीओ, वाणि'य कर विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीमों को साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। ताकि ई-कचरे के ट्रांसपोर्ट को रोका जा सके। दिल्ली से मुरादाबाद तक ई कचरे के ट्रांसपोर्ट का पुराना धंधा रहा है। मुरादाबाद में ई कचरे को लाकर उसे रामगंगा नदी से सटे इलाकों में रात में जलाया जाता है। इसके बाद इससे अलग-अलग मेटल को पृथक करके बेचा जाता है। ई कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। इसके खिलाफ समय-समय पर आवाजें उठती रही हैं। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि रामगंगा नदी के तटीय क्षेत्रों भोजपुर, लालबाग, नवाबपुरा, बरवलान, ताजपुर माफी, रसूलपुर, नंगला खेम आदि क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित भट्ठियों में ई- कचरा जलाने का कार्य किया जा रहा है। डीएम ने इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिस पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने डीएम को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ई-वेस्ट मुख्य रूप से दिल्ली के सीलमपुर इलाके से कवर्ड ट्रकों के माध्यम से गाजियाबाद के रास्ते गजरौला होते हुए मुरादाबाद लाया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग की इस आख्या के बाद डीएम अनुज सिंह ने मुरादाबाद के कांठ, ठाकुरद्वारा, बिलारी के उपजिलाधिकारियों, एसपी यातायात, वाणि'यकर विभाग के अपर आयुक्त और संभागीय परिवहन अधिकारी को ई-कचरे के ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को इन सभी विभागों के साथ समन्वय करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

जेल में बंदी की मौत के मामले में नगर मजिस्ट्रेट करेंगे जांच

मुरादाबाद।

जनपद मुरादाबाद के जिला कारागार में विचाराधीन बन्दी सोमपाल पुत्र पन्नेरा निवासी भैसिया थाना कटघर जनपद मुरादाबाद की 08 नवंबर 2025 को मेडिकल कालेज, मेरठ में उपचार के दौरान हुई मृत्यु की घटना की मजिस्ट्रेरियल जॉच नगर मजिस्ट्रेट विनय पाण्डेय द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रकरण से सम्बन्धित बयान / साक्ष्य अथवा बयान और साक्ष्य कोई भी व्यक्ति अथवा संबंधित व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट परिसर, जनपद मुरादाबाद में 17 जनवरी 2026 तक पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे के मध्य उपस्थित होकर दिये जा सकते है।

नए साल पर दो सराफा दुकान का चोरों ने शटर तोड़कर किया लाखों की चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरा मे कैद

घुरपुर, प्रयागराज। नए साल पर दो सराफा दुकान का चोरों ने शटर तोड़कर किया लाखों की चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरा मे कैद सोनी ज्वेलर्स व लक्की ज्वेलर्स संगमपुर मोड़ पर दुकान है। बीती रात चोरों ने शटर काट लाखों का माल किया पार। भूपेन्द्र सोनी पुत्र नेबू लाल निवासी जगतपुर ने दुकान बंद कर घर चले आये बीती रात चोरों ने शटर काट किया चोरी सुबह ग्रामीणों ने देखा तो दुकानदार भूपेन्द्र सोनी को सूचना दिया। लाखों का माल चोरों ने किया पार सूचना पर पीआरवी मौके पहुंच कर जांच-पड़ताल कर चली गई। सूचना पर थाना प्रभारी मय फोर्स मौके पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन सराफा व्यवसाय के दुकान में चोरी होती है लेकिन खुलासा एक भी नहीं होता है जिससे सराफा व्यवसाय और ग्रामीणों में आक्रोश अगर समय रहते व्यापारीयों के हित के लिए घुरपुर थाने से एक भी सिपाही गस्त पर नहीं निकलते अगर गस्त पर निकलते तो ऐसी घटना नहीं घटती कई घटना घटी लेकिन खुलासा एक भी नहीं हुए ग्रामीण व व्यापारियों का कहना है इस बार भी ऐसा लग रहा है घुरपुर पुलिस चोरी का खुलासा नहीं कर पाएगी। क्योंकि थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच कर कहे कि चोरों को आप लोग पहचानिए तभी पकड़ में आएगी जिससे ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीण व दुकानदारों का कहना है कि पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठाती है जिससे आए दिन चोरियां होती रहती है और पुलिस हाथ पर हाथ धर बैठी रहती है जिससे व्यापारियों में आक्रोश। व्यापारियों कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द खुलासा करें नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी।

एमडीए के सचिव से मिले व्यापारी

मुरादाबाद। संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जोनी और प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज वर्मा से मुलाकात की और व्यापारियों की ओर से समन्वय स्थापित करने की बात कही और कहा कि व्यापारियों को प्राधिकरण की योजनाओं का लाभ दिलाया जाये। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ,प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता ने पटका पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

एसएसपी ने की जनसुनवाई

मुरादाबाद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने शुक्रवार को जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई और महिला हेल्पडेस्क को अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित या शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से अपने थाने से पुलिस कार्यालय न आना पड़े। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है, उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

जीजेयू के तीन खिलाड़ियों का आल इंडिया यूनिवर्सिटी भारोत्तोलन प्रतियोगिता में चयन

मुरादाबाद। 25 से 30 दिसंबर 2025 नॉर्थ ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी भारोत्तोलन प्रतियोगिता चंडीगढ़ में सम्पन्न हुई थी। जिसमें गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए तीन खिलाड़ियों ने अपना स्थान पक्का किया। जिन तीन खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ उनके नाम इस प्रकार है कि रूबी, वर्धमान कॉलेज बिजनौर ने 58 किलो कैटेगरी में 146 किलो वजन उठाया। मानिक चौधरी, जे.एस. हिन्दू डिग्री कॉलेज अमरोहा ने 94 किलो कैटेगरी में 240 किलो वजन उठाया। अमन चौधरी, जे. एस. हिन्दू डिग्री कॉलेज अमरोहा ने 110 किलो कैटेगरी में टोटल 250 किलो वजन उठाया और अपना स्थान ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए सुरक्षित करने में सफलता हासिल की। इस अवसर पर गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के क्रीड़ा सचिव प्रो. एस. एस. रावत ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही प्लाटों का करें क्रय- विक्रय

बहराइच। अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि नगर पालिका परिषद, बहराइच क्षेत्रान्तर्गत प्रायः बिल्डर्स एवं प्रापर्टी डीलर्स द्वारा भूमि को छोटे-छोटे प्लाटों के रूप में बेचा जाता है।

बिल्डर्स एवं प्रापर्टी डीलर्स द्वारा प्लाटों को बेचे जाने से पूर्व न तो नगर पालिका परिषद, बहराइच से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है और न ही सम्बन्धित प्लाट के ले-आउट का नक्शा नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र कार्यालय से पास कराया जाता है जिसके कारण कहीं-कहीं पर नगर पालिका/नजूल से सम्बन्धित भूमि/प्लाट होने की स्थिति में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती को लेकर की गई गोष्ठी की आयोजन

मेजा प्रयागराज। प्रयागराज जनपद के विकास खण्ड उरुवा अंतर्गत ग्राम सभा मिश्रपुर मे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।बिगहनी,रामनगर,प्रयागराज में परम श्रद्धेय भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति स्थल पर उनकी 102 वीं जयंती के अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने हेतु दिनांक 01 जनवरी 2026 को एक विचार संगोष्ठी का आयोजन अमरजीत शर्मा के निजी निवास स्थान (मधुबन) मिश्रपुर, दुबेपुर, सिरसा, मेजा, प्रयागराज में किया गया। संगोष्ठी मे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय, समता एवं जनकल्याण के विचारों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से उनकी जयंती दिनांक 24 जनवरी 2026 को गरिमामय ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया। जयंती कार्यक्रम को सफलतापूर्वक मनाये जाने के लिए कार्ययोजना के निर्माण हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, इस संगोष्ठी में यमुनापार के युवाओं सहित, समाज के अनेक वरिष्ठ समाज सेवी एवम चिंतक शामिल हुए। संगोष्ठी में गरिमामयी उपस्थिति मोहनलाल शर्मा, रामजी शर्मा (मास्टर साहब),शिवदास शर्मा,छविनाथ शर्मा, जगदम्बा प्रसाद शर्मा, नन्दलाल शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा,शशिकांत शर्मा, प्रदीप कुमार वर्मा,अमरजीत शर्मा, मुनेश शर्मा,बृजेश शर्मा, नीरज शर्मा, रोहित शर्मा, सुनील शर्मा, संजय शर्मा, ताड़केश्वर,प्रदीप नन्द शर्मा, मुकेश शर्मा,सन्दीप शर्मा एवं संजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संगोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को आत्मसात करने एवं समाज में समानता, शिक्षा और सामाजिक चेतना को मजबूत करने का आह्वान किया।

मुकदमेबाजी निजी बदला लेने का जरिया नहीं, दहेज उत्पीड़न मामले में अदालत की सुप्रीम टिप्पणी

नई दिल्ली। वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में एक अहम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पति का पत्नी पर आर्थिक या वित्तीय प्रभुत्व अपने आप में क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपराधिक मुकदमेबाजी को निजी बदले या हिसाब चुकता करने का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। यह टिप्पणी अदालत ने एक ऐसे मामले में की, जहां पति के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने पति की अपील स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए कहा कि लगाए गए आरोप कानूनी कसौटी पर खरे नहीं उतरते।

क्रूरता की परिभाषा पर अदालत की टिप्पणी

पीठ ने कहा कि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों में पति का आर्थिक प्रभुत्व जरूर बताया गया है, लेकिन इससे किसी ठोस मानसिक या शारीरिक नुकसान का प्रमाण नहीं मिलता। अदालत ने कहा कि भारतीय समाज में अक्सर घरों में पुरुष वित्तीय मामलों में नियंत्रण रखते हैं, लेकिन केवल इसी आधार पर आपराधिक क्रूरता का मामला नहीं बनता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि खर्चों का हिसाब मांगना या पैसों के उपयोग की जानकारी लेना अपने आप में क्रूरता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी के बीच खर्चों को लेकर विवाद या तकरार विवाह के दैनिक उतार-चढ़ाव का हिस्सा हो सकता है। ऐसे मामलों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने चेतावनी दी कि वैवाहिक मामलों में आरोपों की गहन जांच जरूरी है, ताकि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और न्याय का हनन न हो। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पति पर लगाए गए क्रूरता, मानसिक उत्पीड़न और चोट पहुंचाने के आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं तथा इनमें दुर्भावनापूर्ण मंशा दिखाई देती है।

मोदी सरकार में पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना खत्म होने के कगार पर पहुंची- कांग्रेस

नई दिल्ली।

कांग्रेस ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शुक्रवार को दावा किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पैसे का उचित आवंटन नहीं करने के कारण पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। पार्टी के 'पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने सरकार से आग्रह किया कि इस योजना के लिए हर साल 14 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाए। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ''जवानों को ये भरोसा रहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकार उनका और उनके परिवार का ध्यान रखेगी। लेकिन मोदी सरकार इस भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। 2003 में सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) शुरू किया गया था।

कहा गया था कि ये एक कैशलेस और कैपलेस योजना होगी। उन्होंने दावा किया कि कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि इतने दिनों में पूर्व सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने उसके हिसाब से न कोई व्यवस्था बनाई और न ही पैसे का आवंटन बढ़ाया है। चौधरी का कहना है, ''कैग की रिपोर्ट बताती है कि सेना में जवानों की कमी है, इसलिए जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। इसके अलावा, ईसीएचएस पूरी तरह से तबाही की कगार पर खड़ी है। साल 2023-24 में 13,500 करोड़ रुपये की जरूरत थी, लेकिन बदले में सिर्फ 9,831 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग किसी भी हाल में ईसीएचएस चलाने के लिए सक्षम नहीं है तथा ऐसे में इसे इसे सीडीएस के तहत लाया जाए। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने ईसीएचएस की प्रशासनिक ताकत छीन ली है, उसे वापस किया जाए, 14 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएं और बकाया बिल मंजूर किए जाएं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर ये मांगें पूरी नहीं गईं, तो 30 जनवरी के बाद पूर्व सैनिक दिल्ली आएंगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से मुलाकात कर सरकार से बात करेंगे।

चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, "जवानों को ये भरोसा रहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकार उनका और उनके परिवार का ध्यान रखेगी। लेकिन मोदी सरकार इस भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। 2003 में सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) शुरू किया गया था।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार से एक लाख से ज्यादा नई महिलाओं को मिलेगा लाभ

चंडीगढ़।

हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और निर्णायक कदम उठाते हुए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे का विस्तार कर दिया है। इस विस्तार के साथ ही राज्य की एक लाख से अधिक नई महिलाओं को योजना का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम प्राप्त होगा। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के मानदंड अनुसार एक लाख रुपये सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को पहले की तरह योजना का लाभ मिलता रहेगा। किसी भी पात्र महिला का मौजूदा लाभ न तो रोका गया है और न ही समाप्त किया गया है। 2100 रुपये की सहायता पहले की तरह मिलती रहेगी। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए तीन नई श्रेणियों को जोड़ा है। इन श्रेणियों के लिए पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए और यह लाभ केवल 3 बच्चों तक ही मिलेगा। पहली श्रेणी - जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे है, वे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर लेकर आते है, ऐसी माताओं को भी अब 2100 रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा। दूसरी श्रेणी- जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत कक्षा- 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

तीसरी श्रेणी- पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया से ग्रस्त था और माताओं के अथक प्रयास के बाद वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो ऐसी माताओं को भी 2100 रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के लिए पारिवारिक सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत आधार देने के उद्देश्य से एक नई दूरदर्शी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं और उनके परिवारों को न केवल तत्काल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित वित्तीय संबल भी सुनिश्चित होगा। इस पहल के तहत, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्तमान में जो 2100 रुपए की राशि महिलाओं के खातों में जा रही है, अब इस राशि में से 1100 रुपये सीधे महिलाओं के खातों में जमा होंगे। जबकि शेष 1,000 रुपये राज्य सरकार रेकरिंग डिपॉजिट/फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएगी। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित लाभार्थी महिला को मिलेगा। इतना ही नहीं, लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी, यह भी प्रावधान किया गया है।

योजना का विस्तार करते हुए तीन नई श्रेणियों को जोड़ा गया

एक लाख रुपये सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को पहले की तरह मिलता रहेगा लाभ

पीएम मोदी ने दिलाई बुद्ध के आदर्शों की याद, प्रकाश और कमल प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 3 जनवरी को सुबह लगभग 11 बजे नई दिल्ली के राय पिथोरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक प्रकाश और कमल- जागृत व्यक्ति के अवशेष है, का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि कल, 3 जनवरी, इतिहास, संस्कृति और भगवान बुद्ध के आदर्शों के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए एक विशेष दिन है। सुबह 11 बजे, दिल्ली के राय पिथोरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, प्रकाश और कमल- जागृत व्यक्ति के अवशेष, का उद्घाटन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में पिपरहवा के वे अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं जिन्हें एक सदी से अधिक समय बाद वापस लाया गया है।

इंदौर में पानी नहीं, ज़हर बंटा - राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर तीखा हमला, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में

नई दिल्ली। इंदौर में जल प्रदूषण पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही से जहरीला पानी बंटा, जिससे कई लोगों की मौत हुई और गरीब बेबस रहे। कांग्रेस नेता ने बार-बार की शिकायतों पर भी कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए और इसे जीवन के अधिकार की हत्या बताया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा और मुफ्त इलाज की घोषणा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को इंदौर में कथित जल प्रदूषण की घटना को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जहर बांटने का मामला बताया, जबकि प्रशासन कुंभकर्ण की तरह सो रहा था। इस घटना पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों ने बार-बार गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। राहुल गांधी ने X पर पोस्ट किया कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर-घर मातम है, गरीब बेबस हैं - और ऊपर से बहजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी; सरकार ने घमंड परोस दिया। राहुल ने आगे लिखा कि लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की - फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई?

उन्होंने सवाल किया कि सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये 'फोकट' सवाल नहीं - ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्यप्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है - कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे, और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब-जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत और अन्य के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है। इस बीच, मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और सभी प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की है।

मध्य प्रदेश कुप्रशासन का केंद्र बना, प्रधानमंत्री हमेशा की तरह खामोश हैं - राहुल गांधी

लैब रिपोर्ट से पुष्टि, पाइपलाइन में लीकेज के कारण 14 लोगों की हुई मौत, 200 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती

इंदौर कांड पर खरगे का पीएम मोदी पर तीखा हमला भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी के मोहताज

इंदौर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंदौर में दूषित पानी पीने के कारण कई लोगों की मौत की घटना को लेकर शुक्रवार को दावा किया कि ''जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा की तरह इस मामले पर भी मौन हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली हो रही है। खरगे ने 'एक्स पर पोस्ट किया, ''जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले नरेन्द्र मोदी जी, हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन हैं। यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार आठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। ये शर्मनाक बात है कि यहां पर भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ़ पानी के मोहताज हैं। उन्होंने दावा किया कि 11 साल से देश केवल लंबे-चौड़े भाषण, झूठ-प्रपंच, खोखले दावे, डबल-इंजन की डींगें सुन रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वो गाली-गलौज पर उतर आते हैं। सत्ता के अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं। भाजपा सरकारों के कुशासन पर पूरी मशीनरी पर्दा डालने में जुट जाती है। खरगे ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। उनका कहना था, ''याद दिलाना जरूरी है कि इस मिशन के तहत जल जीवन मिशन का 10 प्रतिशत धन दूषित पानी को साफ़ करने के लिए दिया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ''मोदी सरकार और भाजपा ने ना देश को साफ़ पानी मुहैया कराया है और ना ही स्वच्छ हवा। आम जनता भुगत रही है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप से 10 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। बहरहाल, स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप से छह माह के बच्चे समेत 14 लोगों के दम तोड़ने का दावा किया है। इस दावे की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की है।

कर्नाटक सरकार के सर्वे में ईवीएम हुई पास, बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर सर्वे में ईवीएम पर जनता ने मजबूत भरोसा दिखाया है। राज्य सरकार की एजेंसी का सर्वे के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। सर्वे का शीर्षक नागरिकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार पर किए गए अंतिम सर्वे का मूल्यांकन था। इसमें 83.61 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा है। कुल मिलाकर 69.39 फीसदी प्रतिभागियों ने माना कि ईवीएम सही नतीजे देती है, जबकि 14.22 फीसदी ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई। यह सर्वे 5,100 प्रतिभागियों के बीच 102 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। इसमें बंगलूरू, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूर प्रशासनिक क्षेत्रों को शामिल किया गया। आंकड़ों में सबसे अधिक भरोसा कलबुर्गी में देखा गया, जहां 83.24 फीसदी ने सहमति और 11.24 फीसदी ने पूरी सहमति जताई कि ईवीएम भरोसेमंद है। मैसूर में 70.67 फीसदी ने सहमति और 17.92 फीसदी ने पूर्ण सहमति जताई। बेलगावी में 63.90 फीसदी ने सहमति और 21.43 फीसदी ने पूरी सहमति जताई। बंगलूरू में पूर्ण सहमति सबसे कम 9.28 फीसदी रही। हालांकि 63.67 फीसदी ने सहमति जताई। बंगलूरू में तटस्थ मत सबसे अधिक 15.67 फीसदी रहे।

10 लाख का हेल्थ कवर अब आधार कार्ड -वोटर आईडी पर पंजाब सरकार की बड़ी पहल, 3 महीने में मिलेंगे स्वास्थ्य कार्ड

पंजाब। पंजाब सरकार आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड धारकों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 जनवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे। अधिकांश लाभार्थियों को अगले तीन से चार महीनों के भीतर उनके स्वास्थ्य कार्ड मिल जाएंगे। इस योजना के तहत, लोग राज्य भर के 800 से अधिक निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकेंगे। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनका इलाज निःशुल्क होना चाहिए। उन्होंने इस मामले में मंत्री के आचरण की आलोचना करते हुए इसे अत्यंत अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि इंदौर को पहले स्वच्छ नगर का दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक है। पंजाब में जल सुरक्षा के बारे में बात करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में भूजल में यूरेनियम पाया गया है, वहां राज्य सरकार ने उपचारित नहर के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने आगे कहा कि जल संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों में पड़ोसी गांवों से पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले, शुक्रवार को भगवंत मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क, कैशलेस चिकित्सा उपचार मिलेगा। यह योजना जनवरी में शुरू होने वाली है और पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा। मुख्यमंत्री मान ने स्वास्थ्य विभाग को योजना के शुभारंभ के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया। इसी वर्ष सितंबर में, मान ने एक राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। इस पहल के बारे में बात करते हुए, मान ने कहा कि यह लाभ सीएम हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले, हमने घोषणा की थी कि हम राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे। सीएम हेल्थ कार्ड के साथ, लोग 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए पंजीकरण कल से शुरू होगा। इस स्वास्थ्य कार्ड के तहत, पंजाब के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क और बेहतर उपचार मिलेगा।

उत्तराखंड में सेना के कैंप में लगी आग

जोशीमठ। उत्तराखंड के जोशीमठ जिले में औली रोड पर स्थित एक सेना शिविर के अंदर एक दुकान में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। इमारत से घना धुआं उठता हुआ देखा गया और आपातकालीन दल आग पर काबू पाने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। सेना के जवान स्वयं ही प्रारंभिक दमकल अभियान चलाते नजर आए। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की। इनमें पानी के टैंकर और मैनुअल उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना पर पूर्ण नियंत्रण कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक, पहाड़ी इलाके में चल रही तेज हवा आग बुझाने के काम में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। हवा के तेज झोंके आग को स्टोर के अन्य हिस्सों की ओर धकेल रहे हैं, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद सेना की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

समाधान शिविरों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए- मुख्यमंत्री

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि समाधान शिविरों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुँचाई जाए, जिसमें लोगों को शिविरों के आयोजन का दिन और समय की पूरी जानकारी मिल सके, ताकि वे अपनी समस्याएं दर्ज करवा सकें और उनका समाधान करवा सकें।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश चंडीगढ़ में समाधान शिविर की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में सभी जिला उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतों को जिला उपायुक्त अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ आगे भेजें। साथ ही जब तक किसी शिकायत का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता, तब तक उसे जिला स्तर पर पेंडिंग रखा जाए। बैठक में बताया गया कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक पिछले छह महीनों में कुल 17,699 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। समाधान शिविरों में तय समय सीमा में हल की गई शिकायतों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में भी समाधान शिविरों में आने वाली सभी शिकायतों का तय समय सीमा में निपटान सुनिश्चित करें। प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त और उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) कार्यालयों में प्रत्येक सप्ताह सोमवार और वीरवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें नागरिक अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। यदि समाधान शिविरों में किसी भी स्तर पर अधिकारियों द्वारा लापरवाही पाई गई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जिला अम्बाला के एक गांव में पानी की निकासी से संबंधित समाधान शिविर में प्राप्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त अम्बाला को इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस समिति में संबंधित विभाग के एक्सईएन, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) तथा मार्केट कमेटी का एक कर्मचारी शामिल किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री विवेक कालिया, श्री बी.बी. भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

*** जिला उपायुक्त समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतों को अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ भेजे**

***जब तक किसी शिकायत का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता, तब तक उसे जिला स्तर पर पेंडिंग रखा जाए**

***मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समाधान शिविर की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक**